भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1624

उत्तर देने की तारीख **10.03.2025**

सोमवार, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

तमिलनाडु में आईटीआई का बुनियादी ढांचा

1624. श्री जी. सेल्वमः
श्री सी.एन. अन्नादुरईः
श्री नवसकनी के.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) उक्त राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में आईटीआई के आधुनिकीकरण और के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आईटीआई में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के सुधार और निर्माण के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता राशि क्या है;

(घ) क्या सरकार प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे में सुधार करने और इसे उद्योग की आवश्यकताओं के साथ अधिक संरेखित करने के लिए आईटीआई और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आईटीआई में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उन्हें नवीनतम उद्योग रुझानों और प्रौद्योगिकियों के साथ अद्यतन रखा जा सके; और

(च) क्या सरकार विशेष रूप से अल्पसेवित राज्यों में आईटीआई में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) महोदय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश के युवाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) का कार्यान्वयन करता है।

आईटीआई लंबे समय से घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न ट्रेडों में कुशल जनशक्ति का एक सतत प्रवाह प्रदान कर रहे हैं। आईटीआई में, 168 राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) संरेखित ट्रेडों में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक ट्रेड का एक समर्पित पाठ्यक्रम है। प्रशिक्षण की अवधि छह माह से दो वर्ष तक होती है। पाठ्यक्रमों को ट्रेडों में बुनियादी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि प्रशिक्षु को अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार हेतु तैयार किया जा सके। वर्तमान में, देश में 14,612 आईटीआई स्थापित हैं, जिनमें से 3,316 सरकारी और 11,296 निजी आईटीआई हैं।

यद्यपि आईटीआई संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, फिर भी भारत सरकार समय-समय पर आईटीआई के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाती है।

डीजीटी ने हाल ही में 'औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)' और 'मौजूदा सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन (मॉडल आईटीआई)' योजनाएं कार्यान्वित की थीं, ताकि तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में मौजूदा आईटीआई को उन्नत करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

'स्ट्राइव' योजना के अंतर्गत देश भर में कुल 500 आईटीआई (जिनमें 467 सरकारी और 33 निजी आईटीआई शामिल हैं) का चयन कार्यशालाओं, प्रयोगशालाओं के उन्नयन और आईटीआई की क्षमता-निर्माण के लिए किया गया था। यह योजना 31 मई 2024 को समाप्त हो गई और तमिलनाडु राज्य को 32 आईटीआई (29 सरकारी और 3 निजी) के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए कुल 37.82 करोड़ रुपए (प्रारम्भ से) मंजूर किए गए। तमिलनाडु राज्य से स्ट्राइव योजना के तहत चयनित आईटीआई की सूची **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न है।

एक अन्य योजना, 'मॉडल आईटीआई' योजना में तमिलनाडु राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उपकरण उन्नयन और सिविल कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके 35 चयनित सरकारी आईटीआई को मॉडल आईटीआई में अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई थी। यह योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई, और सरकारी आईटीआई कोयंबटूर के उन्नयन के लिए तमिलनाडु राज्य को कुल 3.99 करोड़ रुपए (केंद्रीय हिस्से के रूप में) की वित्तीय सहायता जारी की गई।

विगत तीन वित्तीय-वर्षों के दौरान, अर्थात् वित्त-वर्ष 2021-22 से वित्त-वर्ष 2023-24 तक, स्ट्राइव योजना के अंतर्गत 20.62 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, और तमिलनाडु राज्य को मॉडल आईटीआई योजना के अंतर्गत 0.49 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) आईटीआई की स्थापना और दिन-प्रतिदिन का प्रशासन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि संबद्धता के लिए मानदंड निर्धारित करना, प्रमाणन के साथ परीक्षा आयोजित करना और पाठ्यक्रम तैयार करना जैसी नीतियां केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हैं।

तमिलनाडु राज्य सहित कई राज्य सरकारों ने सरकारी आईटीआई को आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ प्रौद्योगिकी हब/केंद्रों में बदलने के लिए उद्योगों के साथ सहयोग किया है ताकि उद्योग 4.0 मानकों को पूरा किया जा सके। इन सहयोगों का उद्देश्य सरकारी आईटीआई को अत्याधुनिक तकनीक और उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम से लैस करना है ताकि कौशल अंतराल को कम किया जा सके और छात्रों को उभरते औद्योगिक परिदृश्य की मांगों के लिए तैयार किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कौशल पैकेज के अंतर्गत केंद्रीय बजट 2024 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ-साथ उद्योग के सहयोग से परिणामोन्मुखीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए हब-एंड-स्पोक व्यवस्था के माध्यम से देश भर में 1,000 आईटीआई को उन्नत करना है। इसके अलावा, मौजूदा पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा, और उभरती मांगों को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे।

(ङ) डीजीटी शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) को कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य अनुदेशक प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक कौशल और प्रशिक्षण पद्धति दोनों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उन्हें उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने की तकनीकों से परिचित कराया जा सके। सीआईटीएस तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) (14 सामान्य और 19 महिला) और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 120 संस्थानों (आईटीओटी) (109 राज्य सरकार और 11 निजी) के माध्यम से पेश किया जाता है।

विगत तीन वर्षों (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24) में देश भर के एनएसटीआई और आईटीओटी में सीआईटीएस के अंतर्गत कुल 27,339 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 1,444 प्रशिक्षुओं ने तमिलनाडु राज्य में चेन्नई और त्रिची में स्थित दो एनएसटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

सीआईटीएस के अतिरिक्त, एमएसडीई ने स्ट्राइव परियोजना के अंतर्गत आईटीआई अनुदेशकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:

i. विभिन्न राज्यों के लगभग 27,500 राज्य अधिकारियों, प्राचार्यों और आईटीआई प्रशिक्षकों को एनएसक्यूएफ कार्यान्वयन, प्रबंधन, शिक्षाशास्त्र, उद्यमशीलता, नियोजनीयता और उन्नत व्यापार-संबंधी कौशल में प्रशिक्षित किया गया।

ii. एनएसटीआई और आईटीआई के कुल 463 प्रशिक्षकों ने ड्रोन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

iii. कुल 2,548 प्रशिक्षकों को रोजगार कौशल में सफलतापूर्वक कौशल प्रदान किया गया।

iv. उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई के तहत एक प्रमुख संगठन, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (नीसबड) ने आईटीआई और एनएसटीआई के 1,000 संकाय सदस्यों, प्रशिक्षकों और अनुदेशकों के लिए नियोजनीयता, उद्यमशीलता और जीवन कौशल संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

(च) जी हां। डीजीटी ने पूर्वोत्तर राज्यों में आईटीआई को सहायता प्रदान करने के लिए 'पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना को बढ़ाना (ईएसडीआई)' योजना लागू की थी।

ईएसडीआई योजना में 22 मौजूदा आईटीआई का उन्नयन (प्रति आईटीआई 2 करोड़ रुपए) प्रत्येक आईटीआई में 3 नए ट्रेड स्थापित करके; 28 आईटीआई में कमी वाले बुनियादी ढांचे को पूरा करना (प्रति आईटीआई 2 करोड़ रुपए) नए छात्रावासों, नई चारदीवारी का निर्माण करके, और प्रत्येक आईटीआई में 3 मौजूदा ट्रेडों के लिए पुराने और अप्रचलित उपकरणों और उपकरणों को बदलना; और 34 नए आईटीआई स्थापित करना (प्रति आईटीआई 9.5 करोड़ रुपए) शामिल है। यह योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई, और इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को कुल 308.84 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

इसके अलावा, डीजीटी ने देश भर के वंचित ब्लॉकों में नए आईटीआई खोलने के लिए संबद्धता मानदंडों में छूट भी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य इन वंचित क्षेत्रों में और अधिक आईटीआई की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।

अनुबंध-1

दिनांक 10.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1624 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संदर्भ में।

तमिलनाडु राज्य से स्ट्राइव के अंतर्गत चयनित आईटीआई की सूची:

क्र.सं.	आईटीआई का नाम	सरकारी/निजी	जिला
1.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विरुधुनगर	सरकारी	विरुधुनगर
2.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, त्रिची	सरकारी	तिरुचिरापल्ली
3.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अंबत्तूर	सरकारी	तिरुवल्लुर
4.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डिंडीगुल	सरकारी	डिंडीगुल
5.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चेंगलपट्टू	सरकारी	कांचीपुरम
6.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, थूथुकुडी	सरकारी	थूथुक्कुडी
7.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), नमक्कल	सरकारी	नमक्कल
8.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पेरम्बलुर	सरकारी	पेरम्बलुर
9.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुड्डालोर	सरकारी	कुड्डालोर
10.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सेलम	सरकारी	सलेम
11.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोयंबटूर	सरकारी	कोयंबटूर
12.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मदुरै	सरकारी	मदुरै
13.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिवगंगई	सरकारी	शिवगंगा
14.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तिरुवन्नामलाई	सरकारी	तिरुवन्नामलाई
15.	महिलाओं के लिए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुड्डालोर	सरकारी	कुड्डालोर
16.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, होसुर	सरकारी	कृष्णागिरी
17.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उलुंदुरपेट्टई	सरकारी	कल्लाकुरिची
18.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला, कोयंबटूर	सरकारी	कोयंबटूर
19.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मेट्टूरडम	सरकारी	सलेम
20.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), औंडी	सरकारी	थेनी
21.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नागपट्टिनम	सरकारी	नागपट्टिनम
22.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), मदुरै	सरकारी	मदुरै
23.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पुदुक्कोट्टई	सरकारी	पुदुक्कोट्टई
24.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), डिंडीगुल	सरकारी	डिंडीगुल
25.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गिंडी	सरकारी	चेन्नई
26.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चिदंबरम	सरकारी	कुड्डालोर
27.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरियालुर	सरकारी	अरियालूर
28.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तंजावुर	सरकारी	तंजावुर
29.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुन्नूर	सरकारी	नीलगिरी
30.	डॉन बॉस्को निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	निजी	तिरुचिरापल्ली
31.	रैमको निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	निजी	विरुधुनगर
32.	पी ए सी रामासामी राजा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	निजी	अरियालूर

*****